



WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

मातृभूमि में पीछे छूटे परिवारों पर प्रवास के प्रभावों का एक
समाजशास्त्रीय पूर्वावलोकन

कमल पाण्डेय

सहेयक प्रोफेसर

वर्मा श्यामदुलारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सार

यह शोधपत्र भारत में उभरते प्रवासन पैटर्न और इसके अंतर्गत आने वाले मुद्दों को समझने का एक प्रयास है। वैश्वीकरण, शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के साथ, हाल के दिनों में प्रवासी शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उभरते प्रवासन पैटर्न में व्यापक आर्थिक सुधारों के जवाब में शहरी भारत में प्रवासियों के निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग में सीमित होने को दर्शाया गया है। प्रवासन पर नवीनतम एनएसएस डेटा हाल के प्रवासियों की एक निराशाजनक और भिन्न तस्वीर को प्रकट करता है, जो पाँच वर्ष से पहले प्रवासित हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के बीच अंतर-राज्य प्रवासन में वृद्धि देखी गई है, जो निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोगों के प्रवासन को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय और अंतर-राज्य प्रवासन दर के बीच नकारात्मक अंतर संबंध इसकी पुष्टि करते हैं। निम्न आर्थिक वर्ग में शहरी प्रवासियों की लगातार वृद्धि यह दर्शाती है कि प्रवासन में गरीब वर्गों का वर्चस्व है। यह निष्कर्ष पिछले एनएसएस दौर से पूरी तरह से अलग है, जहाँ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और प्रवासन की प्रवृत्ति के बीच सीधा संबंध देखा गया था। 10 वर्षों की अवधि में प्रवास के इस तरह के भिन्न पैटर्न के कारणों की वास्तव में जांच की जानी चाहिए। पहले की अवधि की तुलना में निचले सामाजिक समूहों का शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रवास होता है। प्रवास पैटर्न में ये सभी भिन्नताएँ सामाजिक-आर्थिक विकास में ग्रामीण-शहरी असमानताओं और बढ़ते शहरीकरण के कारण हैं। वर्तमान विकास और शहरीकरण की वृद्धि, बढ़ती क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए, यह संभावना है कि अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति के कारण भविष्य में शहरी क्षेत्रों में प्रवास और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए, उभरते मुद्दों का पता लगाने, चुनौतियों की पहचान करने और शहरी विकास के लिए नीति स्तर पर आवश्यक मुख्य प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए प्रवास के बदलते पैटर्न की जांच महत्वपूर्ण है। नीति स्तर पर प्रमुख चुनौती प्रवास नीतियों को तैयार करना है, जिन्हें रोजगार और सामाजिक सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों की भलाई को बढ़ाया जा सके।

परिचय

वैश्वीकरण के दौर में भारत में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलावों के मजबूत स्थानिक निहितार्थ हैं। आंतरिक प्रवास पर किए गए अध्ययनों ने 1990 के दशक तक जनसंख्या गतिशीलता में गिरावट का संकेत दिया है (कुंडू, 1996, सिंह, 1998, श्रीवास्तव, 1998, भगत, 2009)¹। इसके विपरीत, सुधार के बाद की अवधि आंतरिक जनसंख्या आंदोलन में वृद्धि की पुष्टि करती है। नवीनतम एनएसएस आंकड़े (2007/08) से पता चलता है कि भारत में आंतरिक प्रवास 1993 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है। विकास के दौरान विभिन्न कारकों की परस्पर क्रिया न केवल गतिशीलता की गति को बढ़ा सकती है बल्कि नए प्रवासन पैटर्न के उद्भव को भी जन्म दे सकती है। प्रवास दर में इस मौजूदा वृद्धि के विपरीत कारण हो सकते हैं। एक ओर बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या दबाव, पर्यावरणीय गिरावट, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आदि आजीविका के विकल्पों को सीमित करती हैं और लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन साथ ही शहरीकरण, बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसर, शिक्षा के स्तर में सुधार, बदलते व्यावसायिक पैटर्न, परिवहन और संचार का विकास स्थानिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने वाली नई प्रेरणा है। फिर भी ऐसे सीमित अध्ययन हैं जो विशेष रूप से सुधार अवधि के बाद प्रवास के बदलते पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, यह भारत में हाल के वर्षों में प्रवास के रुझानों और पैटर्न की और अधिक आलोचनात्मक जांच की मांग करता है। इस शोधपत्र का उद्देश्य भारत में आंतरिक प्रवास के वर्तमान रुझानों और पैटर्न पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है। प्रवास के पैटर्न का विश्लेषण करने की प्रक्रिया पर प्रवास पर मौजूदा शोध और बहस का अवलोकन भी किया गया है। यह शोधपत्र 1999/00 और 2007/08 एनएसएस दौर से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके सुधार के बाद के युग में जनसंख्या गतिशीलता में बदलावों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन में एनएसएसओ निष्कर्षों की तुलना 2011 की जनगणना के परिणामों से भी की गई है।

¹ कुंडू, अमिताभ और गुप्ता, शालिनी (1996): 'प्रवास, शहरीकरण और क्षेत्रीय असमानता', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 28 दिसंबर, पृष्ठ 3391-3398।

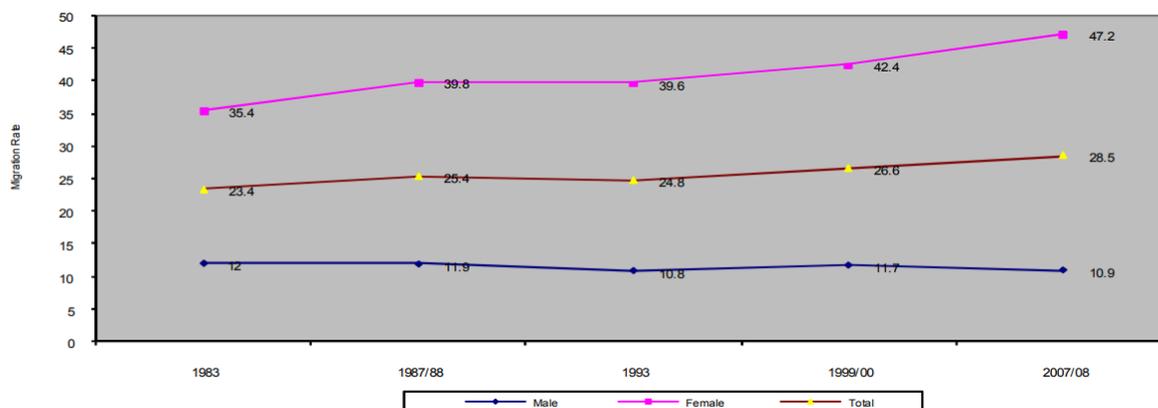
सिंह, एस.पी. और आर.के. अग्रवाल (1998): 'ग्रामीण-शहरी पलायन: पुश और पुल कारकों की भूमिका पर फिर से विचार', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 41 संख्या 4, पृष्ठ 653-667।

श्रीवास्तव, रवि. एस. (1998): 'भारत में प्रवास और श्रम बाजार', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र जर्नल, खंड 41, संख्या 4, पृष्ठ 583-616।

भगत, आर.बी. (2009): 'भारत में आंतरिक प्रवास: क्या निम्न वर्ग अधिक गतिशील है?' 27 सितंबर-2 अक्टूबर 2009 को माराकेच, मोरक्को में आयोजित 26वें आईयूसएसपी सामान्य जनसंख्या सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पेपर।

प्रवासन प्रवृत्तियों का विवरण

1990 के दशक की शुरुआत तक के प्रवासन आँकड़े (जनगणना से) लगभग स्थिरता दर्शाते हैं। एनएसएस के अनुमानों से यह भी पता चलता है कि 1987-88 और 1993 के बीच समग्र जनसंख्या में जनसंख्या गतिशीलता में मामूली गिरावट आई है। इस गिरावट का श्रेय आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को जाता है, जिसका अर्थ है पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक आवागमन और जनसंख्या की बढ़ती गतिहीनता जैसा कि कुछ लेखकों (कुंडू और गुप्ता, 1996)² ने कहा है। फिर भी, सुधार के बाद के दौर में आंतरिक प्रवास में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 1993 में 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007/08 में 28.5 प्रतिशत हो गई है (चित्र-1)



चित्र-1 : लिंग के आधार पर प्रवास दर (एनएसएस, 1983-08)

इसी तरह, 2011 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर भी प्रवास में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। अनुमानित जनसंख्या की तुलना में, जनगणना 2011 की अनंतिम जनसंख्या योग जनसंख्या में 1.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है और यह उम्मीद की जाती है कि यह बढ़ते प्रवास के कारण हो सकता है। यद्यपि समग्र प्रवास प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन लिंग के आधार पर प्रवास पैटर्न में एक महत्वपूर्ण विसंगति देखी जाती है। 1983 से महिला प्रवास में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि 1993 और 1999/00 के बीच पुरुष प्रवास की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है और यह ग्रामीण क्षेत्र में

² कुंडू, अमिताभ और गुप्ता, शालिनी (1996): 'प्रवास, शहरीकरण और क्षेत्रीय असमानता', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 28 दिसंबर, पृष्ठ 3391-3398।

अधिक स्पष्ट है। तालिका-1 से यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष प्रवास 1983 में 7.2 प्रतिशत से घटकर 5.42 प्रतिशत हो गया है, जिसमें 1987 और 1999/00 की अवधि में मामूली वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी इलाकों में भी पुरुषों के पलायन में 1990 के दशक की शुरुआत तक गिरावट देखी गई, हालांकि 1999/00 और 2007/08 के बीच इसमें मामूली वृद्धि हुई। इसलिए, इस बात की और जांच की आवश्यकता है कि पुरुष पलायन दर स्थिर क्यों है जबकि महिला पलायन दर इस अवधि में काफी हद तक बंद हो गई है। यह भी देखा गया है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में पुरुषों का पलायन काफी कम है, जबकि महिलाओं के बीच ऐसा कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच पुरुष पलायन की प्रवृत्ति में भारी अंतर ने कई परस्पर विरोधी तर्कों को जन्म दिया है।

तालिका-1: लिंग और निवास स्थान के अनुसार प्रवास दर, एनएसएस, 1983-08

NSS rounds	Rural		Urban	
	Male	Female	Male	Female
38th (1983)	7.2	35.1	27	36.6
43 rd (1987/88)	7.4	39.8	26.8	39.6
49 th (1993)	6.5	40.1	23.9	38.2
55 th (1999/00)	6.9	42.6	25.8	41.8
64 th (2007/08)	5.42	47.3	25.9	45.62

स्रोत: विभिन्न एनएसएस राउंड से लेखकों की गणना

पुरुष प्रवास में कमी की एक संभावना यह हो सकती है कि गांव स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के माध्यम से रोजगार सृजित होने से ग्रामीण से ग्रामीण प्रवाह कम हो जाता है, जो बदले में समग्र ग्रामीण पुरुष प्रवास को प्रभावित करता है। दूसरी ओर अध्ययनों से पता चलता है कि एनआरईजीए के कार्यान्वयन के बावजूद ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई है (चौधरी, एस. 2011)³।

³ चौधरी, सुभानिल (2011): 'भारत में रोजगार: नवीनतम डेटा क्या दर्शाता है', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, अगस्त, 6, खंड XLVI (32)

इसलिए, पुरुष प्रवास में कमी का एक अन्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी वृद्धि के संदर्भ में समझाया जा सकता है (डी हैन, 2011)⁴। इसके अलावा, एक सवाल उठता है कि बेरोजगारी वृद्धि की दो अवधियों में प्रवास परिदृश्य अलग क्यों है, अर्थात् 1993-00 (रोजगार की वृद्धि दर 1 प्रतिशत से कम है) और 2000-08 (रोजगार की वृद्धि दर 0.17 प्रतिशत है)। यह संभव नहीं है कि बेरोजगारी वृद्धि एकमात्र कारण हो, बल्कि यह आंशिक रूप से घटना की व्याख्या कर सकती है। अन्य संभावित व्याख्या मौसमी प्रवास का कम आंकलन हो सकता है जो पुरुष प्रवास की समग्र वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि (शाइलेंद्र और थॉमस, 1995, एनसीआरएल, 1991; श्रीवास्तव, 1998, कुंडू, 2003)⁵ मौसमी और परिसंचारी प्रवासियों के कारण आंतरिक प्रवास डेटा की रिपोर्टिंग कम है जो श्रम बाजार स्पेक्ट्रम के निचले छोर पर केंद्रित हैं और इस तरह की गतिशीलता वर्षों से लगातार बढ़ रही है (एनसीआरएल, 1991, देशिंगकर और फरिंगटन 2009)⁶। इन संभावनाओं को देखते हुए, वर्तमान परिदृश्य में पुरुष गतिशीलता में गिरावट के सटीक संभावित कारण का उत्तर देना मुश्किल है। पुरुष प्रवास के विपरीत, निवास स्थान की परवाह किए बिना महिला प्रवास में निरंतर वृद्धि देखी गई। यद्यपि प्रवास प्रक्रिया में महिलाओं की अधिकता को मुख्य रूप से विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है, (शांति, 1991, सुंदरी, 2005; अराया एट अल. 2006)⁷ द्वारा किए गए उभरते अध्ययनों से पता चलता है कि विवाह से लेकर अन्य कारणों, विशेषकर आर्थिक कारणों से महिला प्रवास का पैटर्न बदल रहा है। इसलिए, प्रवास में वर्तमान प्रवृत्तियों के कारणों का पता लगाने के लिए, दूरी के हिसाब से प्रवास के बाद प्रवास के अन्य आयामों पर एक नज़र डालना महत्वपूर्ण है।

⁴ डी हान ए (2011): समावेशी विकास? भारत में श्रमिक प्रवास और गरीबी, कार्य पत्र संख्या 513, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान।

⁵ शांति, के. (1991): 'महिलाओं के आर्थिक प्रवास से संबंधित मुद्दे', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 34, संख्या 4।

शैलेन्द्र एच.एस. और पी. थॉमस 1995: 'गैर-कृषि रोजगार: पश्चिमी भारत के अर्ध-शुष्क गांव में प्रकृति, परिमाण और निर्धारक', भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 50, संख्या 3, पृष्ठ 410-416।

⁶ देशिंगकर, पी. और फरिंगटन, जे. (2009): 'ग्रामीण भारत में सर्कुलर माइग्रेशन और मल्टी लोकेशनल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

⁷ शांति, के. (1991): 'महिलाओं के आर्थिक प्रवास से संबंधित मुद्दे', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 34, संख्या 4।
सुंदरी, एस (2005): 'आजीविका रणनीति के रूप में प्रवास: एक लिंग परिप्रेक्ष्य', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 28 मई-4 जून।

दूरी के अनुसार प्रवास (प्रकार)

भारी प्रमाण दर्शाते हैं कि कम दूरी के प्रवास का प्रभुत्व है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति देश में कम से कम शहरी प्रवासियों के बीच धीरे-धीरे बदल रही है। तालिका-2 दर्शाती है कि 2007/08 में शहरी क्षेत्र में पुरुष प्रवास अंतर-जिला (39.31 प्रतिशत) में अधिक है, उसके बाद अंतर-राज्यीय (31.9 प्रतिशत) है। इसी तरह, महिलाओं के लिए अंतर-जिला (42.51 प्रतिशत) और उसके बाद अंतर-जिला प्रवास (38.32 प्रतिशत) प्रवास प्रवाह पर हावी है। तालिका समय के साथ प्रवास के पैटर्न में कई बदलाव लाती है। लिंग के बावजूद अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय प्रवास में वृद्धि के साथ-साथ अंतर-राज्यीय गतिशीलता में कमी देखी गई है। और शहरी क्षेत्रों में अंतर-राज्यीय पुरुष प्रवास में वृद्धि 1999/00 में 23.57 प्रतिशत से बढ़कर 2007/08 में 31.9 प्रतिशत हो गई है।

तालिका-2: विभिन्न दूरी श्रेणियों में प्रवासियों का प्रतिशत वितरण, एनएसएस, 1999/00 और 2007/08 (अवधि < 5 वर्ष)

Types of migration	Total		Rural		Urban	
	M	F	M	F	M	F
2007/08						
Intra-district	37.59	59.05	52.5	69.57	27.71	38.32
Inter-district	34.71	30.33	27.77	24.15	39.31	42.51
Inter-state	26.27	10.33	17.77	6.07	31.9	18.72
International	1.43	0.29	1.95	0.21	1.08	0.45
1999/00						
Intra-district	47.78	63.09	59.84	71.98	37.77	43.47
Inter-district	30.94	26.64	23.06	21.18	37.47	38.67
Inter-state	19.72	9.94	15.08	6.53	23.57	17.46
International	1.56	0.34	2.01	0.31	1.19	0.4

स्रोत: लेखक द्वारा एनएसएस के विभिन्न दौरों से की गई गणना

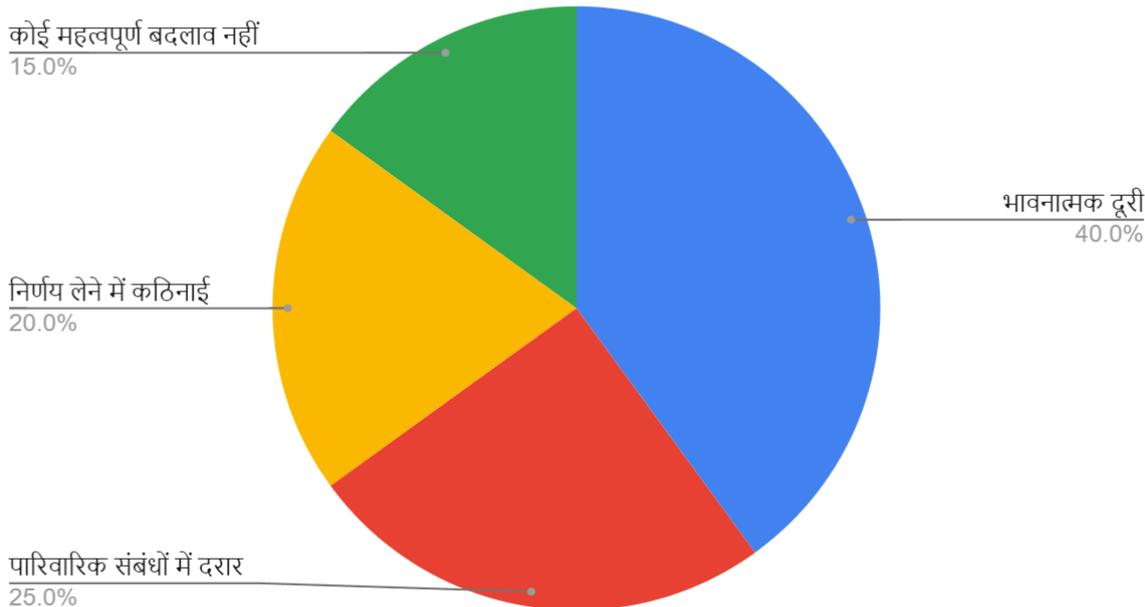
अंतर-राज्यीय प्रवास में सापेक्ष वृद्धि इस बात का संकेत है कि प्रवास की प्रवृत्ति आर्थिक कारणों की ओर बढ़ रही है (सिंह, 2009)⁸। बेहतर रोजगार के अवसरों के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग विकसित राज्यों के शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं। साथ ही, सूक्ष्म अध्ययनों की बढ़ती मात्रा से पता चलता है कि गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय कमजोरियों के कारण अविकसित राज्यों के निम्न सामाजिक-आर्थिक तबके के लोग रोजगार पाने की तलाश में विकसित राज्यों की ओर पलायन करते हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय गतिशीलता की बढ़ती मात्रा के कारणों (धक्का/खींच) के बारे में कहना अभी प्रारंभिक है, बल्कि अंतर-राज्यीय प्रवास में शामिल लोगों के प्रकार को समझने के लिए अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रवास के रुझानों की जांच करने का दूसरा तरीका धारा के अनुसार है क्योंकि यह इन प्रकार के प्रवास के बदलते पहलुओं पर कुछ प्रकाश डालता है।

तालिका-3:

बदलाव के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
भावनात्मक दूरी	40	40%
पारिवारिक संबंधों में दरार	25	25%
निर्णय लेने में कठिनाई	20	20%
कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं	15	15%

⁸ सिंह, डी. पी. (2009), 'गरीबी और पलायन: क्या स्थानांतरण मदद करता है?' कुंडू ए. (संपादक), भारत: शहरी गरीबी रिपोर्ट 2009, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

उत्तरदाताओं की संख्या and प्रतिशत (%)



विश्लेषण:

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 40% परिवारों ने प्रवास के कारण भावनात्मक दूरी का अनुभव किया है। 25% परिवारों ने पारिवारिक संबंधों में दरार महसूस की, जबकि 20% ने निर्णय लेने में कठिनाई का सामना किया। केवल 15% उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने प्रवास के बाद कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या भावनात्मक बदलाव महसूस नहीं किया।

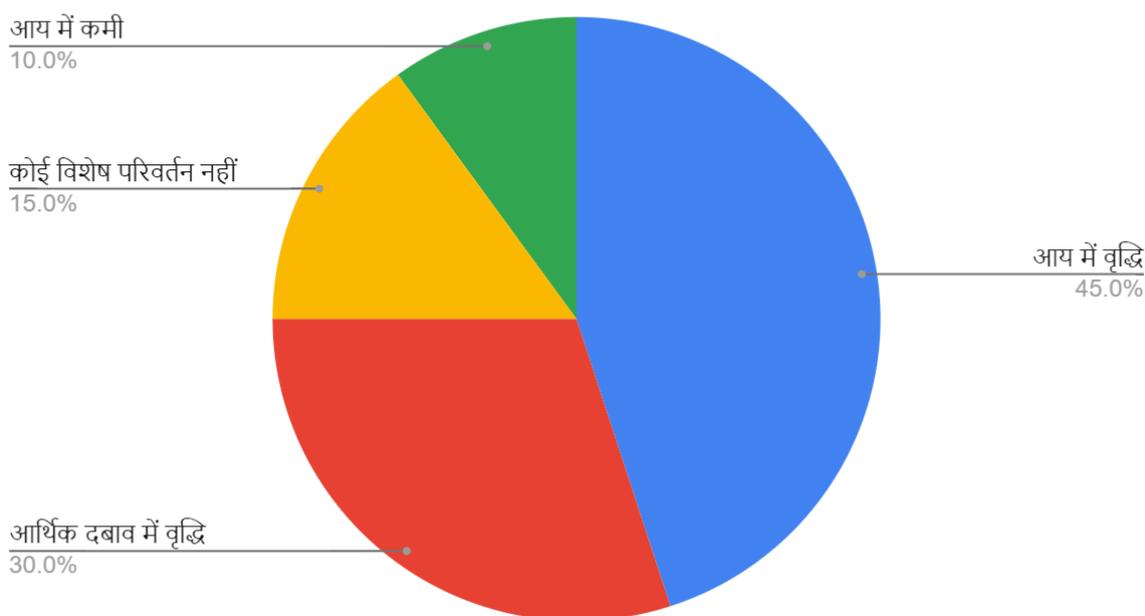
व्याख्या:

यह डेटा दर्शाता है कि प्रवास का सबसे बड़ा प्रभाव परिवारों के भावनात्मक बंधनों पर पड़ा है। जिन परिवारों के सदस्य प्रवास कर गए हैं, वे भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। इसके अलावा, पारिवारिक निर्णयों में सामूहिकता की कमी के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। पारिवारिक संरचना और संबंधों में स्पष्ट दरारें आई हैं।

तालिका-4:

आर्थिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
आय में वृद्धि	45	45%
आर्थिक दबाव में वृद्धि	30	30%
कोई विशेष परिवर्तन नहीं	15	15%
आय में कमी	10	10%

उत्तरदाताओं की संख्या and प्रतिशत (%)



विश्लेषण:

45% परिवारों ने प्रवास के बाद आय में वृद्धि देखी है, जबकि 30% ने आर्थिक दबाव में वृद्धि महसूस की है। 15% परिवारों ने अपनी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा, और 10% परिवारों की आय में कमी आई है।

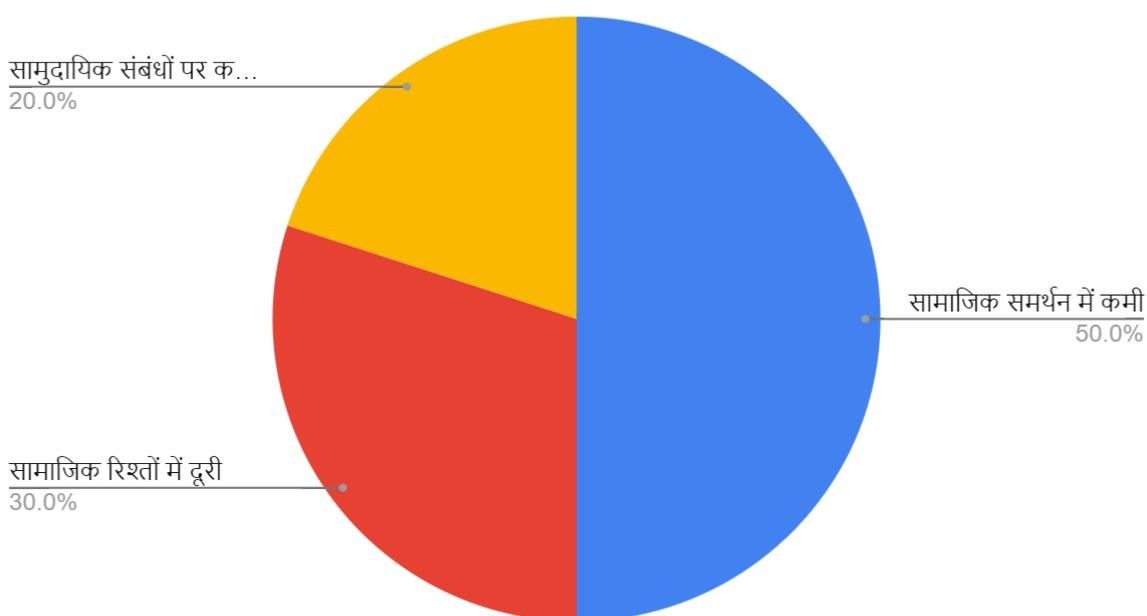
व्याख्या:

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रवास से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। हालांकि, दूसरी तरफ, कई परिवारों ने आर्थिक दबाव का अनुभव किया है, जो मुख्य रूप से प्रवास के बाद वित्तीय सहायता की कमी या आर्थिक अस्थिरता के कारण हो सकता है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आर्थिक लाभ नहीं हुआ और उनकी स्थिति स्थिर रही।

तालिका-5:

सामाजिक समर्थन का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
सामाजिक समर्थन में कमी	50	50%
सामाजिक रिश्तों में दूरी	30	30%
सामुदायिक संबंधों पर कोई असर नहीं	20	20%

उत्तरदाताओं की संख्या and प्रतिशत (%)



विश्लेषण:

50% उत्तरदाता मानते हैं कि प्रवास के बाद उन्हें सामाजिक समर्थन में कमी महसूस हुई है। 30% ने कहा कि उनके सामाजिक रिश्तों में दूरी आई है, जबकि 20% का मानना है कि प्रवास के बाद उनके सामुदायिक संबंधों पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा।

व्याख्या:

प्रवास के कारण परिवारों को सामाजिक समर्थन की कमी का सामना करना पड़ा है। जब परिवार के सदस्य प्रवास करते हैं, तो उनकी गैर-मौजूदगी से पीछे छूटे हुए परिवारों को सामाजिक और सामुदायिक सहायता में कमी महसूस होती है। इससे उनके सामाजिक रिश्तों में भी दूरी आ जाती है, जिससे वे अपने समुदाय से धीरे-धीरे अलग-थलग पड़ सकते हैं।

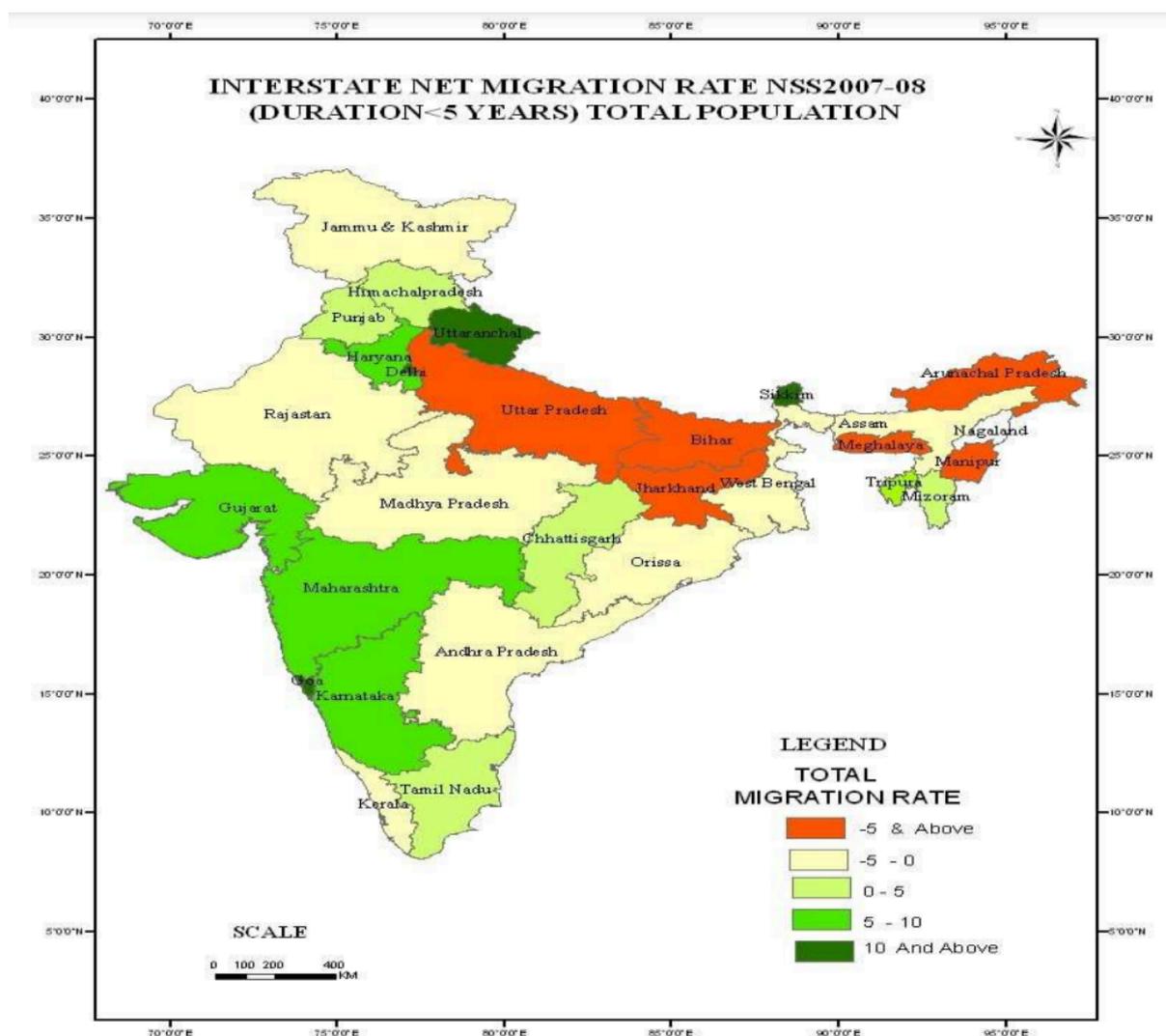
संपूर्ण निष्कर्ष:

इन तीन तालिकाओं के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि प्रवास का प्रभाव परिवारों पर सामाजिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामुदायिक स्तर पर पड़ता है। प्रवास के कारण भावनात्मक दूरी और पारिवारिक संबंधों में दरार जैसे सामाजिक बदलाव सामने आए हैं। आर्थिक दृष्टि से, कुछ परिवारों ने आय में वृद्धि का अनुभव किया, जबकि अन्य परिवारों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, प्रवास के कारण सामाजिक समर्थन में कमी और सामाजिक रिश्तों में दूरी आई है, जो सामुदायिक संबंधों को प्रभावित करता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, प्रवास के प्रभावों का अध्ययन दर्शाता है कि यह केवल एक आर्थिक या भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और भावनात्मक परिणाम भी होते हैं, जो परिवारों की संरचना और सामुदायिक संबंधों को गहराई से प्रभावित करते हैं।

अंतर-राज्यीय शुद्ध प्रवास

तालिका-2 से यह पहले ही देखा जा चुका है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अंतरराज्यीय पुरुष प्रवास में वृद्धि हुई है। विकास के स्तर में स्थानिक विविधता को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि विभिन्न राज्यों के बीच अंतरराज्यीय प्रवास में काफी भिन्नता होगी। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च स्तर की गरीबी, निरक्षरता आदि वाले राज्यों में अंतरराज्यीय गतिशीलता आम तौर पर कम होती है (कादी, एट अल.1988) हालांकि, हाल के वर्षों में पिछड़े राज्यों से लोगों का पलायन बढ़ रहा है, जो अकुशल और कम शिक्षित लोगों के प्रवास को दर्शाता है।



अंतरराज्यीय शुद्ध प्रवास की मात्रा मानचित्र-1 में प्रस्तुत की गई है। यह पाया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब जैसे विकसित राज्यों में शुद्ध प्रवास दर सकारात्मक है, जो इन राज्यों में लोगों के आने का संकेत देता है। इसे राज्यों के औद्योगीकरण, रोजगार की उपलब्धता और सामाजिक विकास के संदर्भ में समझाया जा सकता है। इसके विपरीत, जनसंख्या के बड़े संकेन्द्रण, असमानता और गरीबी आदि के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्य और उत्तर-पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासियों की आपूर्ति करते हैं।

प्रवासी कौन हैं?

आर्थिक विशेषताएँ चूँकि, प्रवासन मुख्यतः गरीब राज्यों से होता है, इसलिए इस अवधि में प्रवासियों की विशेषताओं को देखना आवश्यक है। हालाँकि प्रवासन की स्थानिक विशेषताएँ प्रवासन के लिए प्रेरणाओं पर कुछ प्रकाश डालती हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि प्रवासन संकट के कारण होता है या विकास के कारण। इसलिए, गरीबी और प्रवासन के बीच संबंध को समझने के लिए गरीबी और उनके द्वारा किए जाने वाले रोजगार के प्रकार के संदर्भ में प्रवासियों की आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

प्रवासी श्रमिकों का औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी, 2004)

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड - 2004 के आधार पर प्रवासियों का व्यावसायिक वर्गीकरण तालिका-8 में दर्शाया गया है। 2007/08 के एनएसएस अनुमानों से पता चलता है कि प्रवास से पहले और बाद में अन्य व्यावसायिक श्रेणियों की तुलना में कृषि में कार्यरत महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है, उसके बाद विनिर्माण, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य आदि का स्थान है। इसके विपरीत, पुरुष प्रवासी का अनुपात विनिर्माण (25.99 प्रतिशत) में अधिक है, उसके बाद व्यापार और वाणिज्य (24.5 प्रतिशत) और कृषि (12 प्रतिशत) का स्थान है, जबकि प्रवास से पहले कृषि में यह अनुपात अधिक था (28.4 प्रतिशत)।

हालांकि, रोजगार के पैटर्न में ग्रामीण-शहरी विभेद मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासी का अनुपात कृषि में अधिक है, खासकर महिलाओं में, जो कृषि के महिलाकरण को दर्शाता है। परिवार की आर्थिक आवश्यकता, शिक्षा और कौशल की कमी महिलाओं को कृषि गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र (पीए+शिक्षा+स्वास्थ्य) में महिलाओं की संख्या अधिक है, उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का स्थान है। विनिर्माण क्षेत्र में कृषि उद्योग शामिल हैं, जिसमें कपड़ा, परिधान, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, पेय पदार्थ और खाद्य उत्पाद, तंबाकू, कागज उत्पाद आदि शामिल हैं और इसलिए इनमें अधिकांश महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य में भी महिलाओं के रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि पुरुष प्रवास के मामले में विनिर्माण और व्यापार और वाणिज्य दोनों में बराबर और उच्चतम हिस्सा है जो क्रमशः 28 प्रतिशत है।

पलायन से पहले और बाद में प्रवासी श्रमिकों के औद्योगिक वर्गीकरण में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। पलायन से पहले और बाद में कृषि में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में महिला प्रवासी का अनुपात पलायन से पहले 82 प्रतिशत था जो पलायन के बाद घटकर 77 प्रतिशत रह गया। शहरी क्षेत्र में कृषि में महिला प्रवासी श्रमिकों की संख्या में अचानक 35.3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं कृषि कार्य छोड़कर शहरी क्षेत्र में पलायन कर रही हैं और बड़े पैमाने पर विनिर्माण और अन्य सेवा क्षेत्र में शामिल हो रही हैं। कृषि में महिला प्रवास में कमी के साथ विनिर्माण और व्यापार में हिस्सेदारी में वृद्धि और निजी घरों में घरेलू कामगार के रूप में श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। पुरुषों के मामले में भी यही पैटर्न देखा गया है। कृषि के विपरीत, अन्य प्रकार के व्यवसायों में प्रवासी श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि हुई है। विनिर्माण श्रमिकों, व्यापार और वाणिज्य श्रमिकों और शिक्षा में प्रवासी महिलाओं के मामले में पलायन के बाद उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। निजी घरों में श्रमिकों के रूप में महिला प्रवासी में पलायन के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर शहरी क्षेत्र में 1.3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक। प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के साथ, कुछ हद तक शिक्षित महिलाएँ घर से बाहर अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाती हैं। इसलिए,

बच्चों और वृद्धों की देखभाल के लिए, अधिकांश महिलाएँ काम के दोहरे बोझ को कम करने के लिए घरेलू नौकर रखती हैं। इसलिए, हाल के वर्षों में घरेलू नौकरों की माँग बहुत बढ़ गई है क्योंकि यह लगभग हर व्यक्ति के जीवन की ज़रूरत बन गई है। आस-पास के गाँवों की अधिकांश अविवाहित महिलाएँ निम्न जाति और निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं जो घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए शहरों में चली गई हैं। सामाजिक नेटवर्क भी इस संदर्भ में एक सुविधाजनक कारक के रूप में कार्य करता है।

प्रवासियों के रोजगार पैटर्न में लैंगिक असमानता कृषि में महिलाओं की प्रधानता को दर्शाती है जबकि अन्य क्षेत्रों में पुरुषों की सांद्रता है। व्यापार और वाणिज्य के बाद परिवहन और संचार में पुरुष प्रवासियों की सांद्रता अधिक है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र में लिंग के आधार पर अनुपात समान है। उपर्युक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

1. कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में प्रवासियों की घटती श्रम शक्ति भागीदारी आर्थिक विकास का संकेत है। आर्थिक विकास के साथ, कोई यह उम्मीद कर सकता है कि रोजगार कृषि से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगा।

2. गैर-कृषि रोजगार पुरुष श्रमिकों के पक्ष में भारी पक्षपाती है। सिकुड़ती आजीविका और कौशल की अनुपस्थिति के कारण कृषि में महिलाओं की अधिकता है। परिणामस्वरूप, कृषि कार्यबल और मजदूरी का काम तेजी से महिलाओं द्वारा संचालित होता जा रहा है। कृषि में महिलाओं की अधिकता को एक नकारात्मक संकेत माना जाना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रतिकूल स्थिति और बढ़ती असमानता और गरीबी का संकेत है (विश्व बैंक, 1991)।

3. प्रवासी के रोजगार पैटर्न में ग्रामीण-शहरी अंतर मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह औद्योगिक और सेवा क्षेत्र है। गैर-कृषि गतिविधियों में प्रवासियों की बढ़ती श्रम शक्ति भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रवासी श्रमिक उच्च पारिश्रमिक के

लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना पसंद करते हैं। इसके अलावा, यह भी कहा जा सकता है कि व्यापार और वाणिज्य, विनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का प्रवाह है।

4. प्रवास के बाद के चरण में निजी घरों में कार्यरत व्यक्तियों के रूप में महिलाओं का अनुपातिक रूप से उच्च प्रतिशत पाया गया। इस श्रेणी की महिलाएँ मुख्य रूप से घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं। सरासर आर्थिक आवश्यकताएँ उन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करती हैं। घरेलू कामगारों पर कई अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी ने उन्हें शहरी क्षेत्रों में पलायन करने और किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया (बेहरा, 1991; बनर्जी, 1985; कल्पगम, 1994, घोष, 1996; भट्ट, 2001)। नीता (2004) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि घरेलू सेवा के लिए पलायन मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित घटना है, जहाँ महिलाएँ पलायन और परिवार के अस्तित्व में प्राथमिक भूमिका निभाती हैं। पलायन के बाद महिलाओं की बढ़ती श्रम शक्ति भागीदारी से पता चलता है कि महिलाएँ अब निष्क्रिय प्रवासकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारी या शायद स्वतंत्रता की भावना के कारण नौकरी की तलाश करती हैं। इस स्तर पर पलायन के विशिष्ट कारणों और समय के साथ इसके बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है ताकि बदलते पलायन पैटर्न को समझा जा सके।

निष्कर्ष और नीति सुझावों का सारांश

यह शोधपत्र प्रवासियों की वर्तमान प्रवृत्तियों, पैटर्न और विशेषताओं को दर्शाता है। अध्ययन से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर सामने आए। प्रवासन पर नवीनतम जानकारी हाल के प्रवासियों की एक निराशाजनक तस्वीर को उजागर करती है, जिसमें पुरुष प्रवास में कमी, शहरी क्षेत्र में पुरुषों के बीच अंतरराज्यीय गतिशीलता में वृद्धि, निम्न आर्थिक वर्ग में शहरी प्रवासियों की लगातार वृद्धि और विशेष रूप से महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी में गिरावट शामिल है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष प्रवास में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शायद स्थिर रोजगार वृद्धि श्रम गतिशीलता को हतोत्साहित कर सकती है और एलएफपीआर को भी प्रभावित कर सकती है। पुरुष प्रवास में कमी

नरेगा के सफल कार्यान्वयन का परिणाम भी हो सकती है या मौसमी प्रवास में वृद्धि के कारण हो सकती है, जिसे डेटा में पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के तहत बनाए गए अल्पकालिक रोजगार के अवसर मौसमी और संकट से संबंधित प्रवास को कम करते हैं, लेकिन यह ग्रामीण से शहरी प्रवाह को कम करने में सक्षम नहीं है।

यह शहरी क्षेत्रों में निम्न आर्थिक पंचम में प्रवास दर में लगातार वृद्धि से स्पष्ट है। इस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक और गैर-कृषि रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि गरीबों के बीच ग्रामीण से शहरी गतिशीलता को रोका जा सके। बढ़ती क्षेत्रीय असमानताएं और पारिस्थितिक ताकतों पुरुषों के बीच अंतरराज्यीय प्रवास में उल्लेखनीय वृद्धि लाती हैं। हालांकि, डेटा की सीमाएं पर्यावरणीय ताकतों के संबंध में श्रम प्रवास को आंशिक रूप से समझाती हैं। मौजूदा अध्ययनों के मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि समय के साथ मौसमी प्रवास में वृद्धि हुई है, जो सर्वेक्षण डेटा में पूरी तरह से दर्ज नहीं है। इसके अलावा, चुनौती यह है कि हम अपने अध्ययनों में इस तरह के आंदोलनों को शामिल करने वाले अधिक व्यापक प्रवास परिदृश्य को कैसे शामिल करेंगे। शोध के पक्ष में, अंशकालिक और मौसमी गतिविधियों को शामिल करने वाले व्यवसायों पर अधिक अलग-अलग डेटा की तत्काल आवश्यकता है।

जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों को अतिरिक्त मॉड्यूल (देशिंगकर, 2009)⁹ के साथ पूरक करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब वर्ग में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ मौसमी प्रवास में वृद्धि की भी उम्मीद की जा सकती है। आजीविका और अस्तित्व के लिए, दुबले मौसम में कृषि श्रमिक अस्थायी बदलाव कर सकते हैं। तब मौसमी प्रवासियों का गरीबी से सकारात्मक संबंध स्थापित होगा। इस संबंध में, शहरी योजनाकारों और नीति निर्माताओं को ऐसे आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है। भारत में तेजी से शहरी विकास होने की संभावना है और शहरी क्षेत्रों में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। यह उम्मीद की जाती है कि 2021 तक

⁹ देशिंगकर, पी. और फरिंगटन, जे. (2009): 'ग्रामीण भारत में सर्कुलर माइग्रेशन और मल्टी लोकेशनल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

शहरी आबादी कुल आबादी का लगभग 40% हो जाएगी (शहरी बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2005)¹⁰। शहरी क्षेत्र में प्रवास का हिस्सा 1999/00 में 33% से बढ़कर 2007/08 में 35% हो गया। वर्तमान विकास और शहरीकरण की वृद्धि को देखते हुए यह संभावना है कि भविष्य में शहरी क्षेत्रों में प्रवास और अधिक बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में विकास की कम दर और आय में अनिश्चितता, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों में कमी ने अविकसित क्षेत्रों से पलायन को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश प्रवासी शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाते हैं। इसलिए, नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि वे शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी के रोजगार और कल्याण से जुड़ी प्रवास नीतियां तैयार करें। नीतियों को स्पष्ट रूप से शहरी गरीब प्रवासियों की समस्या को संबोधित करते हुए लागू किया जाना चाहिए, जो बड़े पैमाने पर शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में समायोजित हो रहे हैं।

यह तर्क दिया गया है (देशिंगकर, 2009)¹¹ कि यद्यपि भारत में विकासशील दुनिया में गरीब समर्थक कार्यक्रमों की सबसे व्यापक प्रणालियों में से एक है, लेकिन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर निवास प्रमाण की आवश्यकताओं के कारण पूरे समय इन तक पहुँच नहीं पाते हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न, सरकारी स्कूल, अस्पताल और अन्य गरीब समर्थक योजनाएँ उनके लिए दुर्गम हैं। इन्हें और अधिक लचीला बनाने की तत्काल आवश्यकता है और विभिन्न राज्यों को इस पर सहमति बनाने की आवश्यकता है कि यह कैसे किया जाना चाहिए। हालाँकि प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून मौजूद हैं, लेकिन खास तौर पर भारत में नियोक्ताओं और बिचौलियों द्वारा इन्हें व्यापक रूप से नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है और अशिक्षित प्रवासियों

¹⁰ शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2005), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) टूलकिट, नई दिल्ली।

¹¹ देशिंगकर, पी. और फरिंगटन, जे. (2009): 'ग्रामीण भारत में सर्कुलर माइग्रेशन और मल्टी लोकेशनल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

में श्रमिक के रूप में अपने अधिकारों के बारे में अज्ञानता है। आम जनता, नीति निर्माताओं और खुद प्रवासियों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

चिंता का एक और प्रमुख क्षेत्र महिला प्रवास पर ध्यान केंद्रित करना है क्योंकि महिला प्रवास का पैटर्न विवाह से लेकर रोजगार और शिक्षा के कारणों में बदलता रहता है। प्रवास और लिंग से संबंधित शोध और नीति क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर बना हुआ है, इसलिए, लिंग के दृष्टिकोण से प्रवास को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। भारत में आंतरिक प्रवास में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी इसकी गतिशीलता के अधीन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

संदर्भ सूची:

- आचार्य, एस (2003): 'कंबोडिया में प्रवासन पैटर्न-कारण और परिणाम', प्रवासन और विकास पर तदर्थ विशेषज्ञ समूह की बैठक, 27-29 अगस्त, बैंकॉक।
- एक्शनएड (2005): 'भूख से पीड़ा तक... एक यात्रा: ईट भट्टों में प्रवासी श्रमिक - हस्तक्षेप रिपोर्ट। हैदराबाद एक्शन एड।
- अफसर, आर (2003): 'गरीबी, विकास और जनसंख्या गतिशीलता की गतिशीलता: बांग्लादेश मामला', प्रवासन और विकास पर तदर्थ विशेषज्ञ समूह की बैठक, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित, बैंकॉक, 27-29 अगस्त।

- आर्य.एस और अनुम्पा रॉय (2006): "गरीबी, लिंग और प्रवासन", सेज प्रकाशन।
- एशियाई विकास बैंक (2001): 'कंबोडिया, मनीला में सहभागी गरीबी मूल्यांकन',
http://www.adb.org/Documents/Books/Participatory_poverty/Participatory_poverty/pdf
.
- भगत, आर.बी. (2009): 'भारत में आंतरिक प्रवास: क्या निम्न वर्ग अधिक गतिशील है?' 27 सितंबर-2 अक्टूबर 2009 को माराकेच, मोरक्को में आयोजित 26वें आईयूएसएसपी सामान्य जनसंख्या सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पेपर।
- भगत, आर.बी. (2010): 'भारत में आंतरिक प्रवास: क्या वंचित वर्ग अधिक प्रवास कर रहा है?' एशिया-प्रशांत जनसंख्या जर्नल, खंड 25, संख्या 1, पृष्ठ 27-45।
- चौधरी, सुभानिल (2011): 'भारत में रोजगार: नवीनतम डेटा क्या दर्शाता है', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, अगस्त, 6, खंड XLVI (32)
- दयाल, एच और ए.के.करण (2003): 'झारखंड से श्रमिक प्रवास', मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली।
- डी हान ए (1997): 'ग्रामीण-शहरी प्रवास और गरीबी: भारत का मामला', आईडीएस बुलेटिन, खंड 28, संख्या 2, पृष्ठ 35-47।
- डी हान ए (2011): समावेशी विकास? भारत में श्रमिक प्रवास और गरीबी, कार्य पत्र संख्या 513, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान।

- देशिंगकर, पी. और फरिंगटन, जे. (2009): 'ग्रामीण भारत में सर्कुलर माइग्रेशन और मल्टी लोकेशनल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- देशिंगकर, प्रिया (2009): भारत में सर्कुलर आंतरिक प्रवास और विकास, essays.ssrc.org/acrossborders/wp-content/uploads/2009/08/ch8.pdf
- देशिंगकर, पी. और डी.स्टार्ट (2003): 'आजीविका, मुकाबला, संचय और बहिष्कार के लिए मौसमी प्रवास', वर्किंग पेपर नंबर 220, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लंदन।
- गजदार, एच (2003): 'पाकिस्तान में प्रवासन मुद्दों की समीक्षा', एशिया में प्रवासन, विकास और गरीब समर्थक नीति विकल्पों पर क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया पेपर, बांग्लादेश शरणार्थी प्रवासी आंदोलन अनुसंधान इकाई, बांग्लादेश/डीएफआईडी यूके, ढाका द्वारा 22-24 जून को आयोजित किया गया।
- जेम्स, के (2002): 'आंध्र प्रदेश में प्रवासन गतिशीलता: दशकीय जनगणना से साक्ष्य', वैश्वीकरण की दुनिया में श्रम गतिशीलता पर एक सेमिनार में प्रस्तुत किया गया पेपर: वैचारिक और अनुभवजन्य मुद्दे। कादी, ए.एस. और शिवमूर्ति, एम (1988): भारत में अंतरराज्यीय प्रवासन: 1971-81। जनसंख्या में कनाडाई अध्ययन, खंड 15, संख्या 1, पृष्ठ 37-50।
- करण, ए (2003): 'ग्रामीण बिहार से पलायन के बदलते पैटर्न', जी. अय्यर (संपादक) प्रवासी श्रम और भारत में मानवाधिकार, नई दिल्ली: कनिष्क प्रकाशक, पृष्ठ 102-39।
- कुंडू, ए (2003): 'शहरीकरण और शहरी शासन, नवउदारवाद से परे एक परिप्रेक्ष्य की खोज,' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, XXXVIII (29), पृष्ठ 3079-98।

• कुंडू, अमिताभ और गुप्ता, शालिनी (1996): 'प्रवास, शहरीकरण और क्षेत्रीय असमानता', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 28 दिसंबर, पृष्ठ 3391-3398।

• कुंडू, ए. (1997): '1990 के दशक में रोजगार की प्रवृत्तियाँ और संरचना: शहरी विकास के लिए निहितार्थ', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 32, संख्या 4, पृष्ठ 1399-1405।

कुंडू, ए. (2011): "भारत में शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और प्रक्रियाएँ", शहरीकरण और उभरती जनसंख्या के मुद्दे,

• शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2005), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) टूलकिट, नई दिल्ली।

• मित्रा, ए. और मयूमी मुरायामा (2008): 'ग्रामीण से शहरी प्रवास: भारत के लिए एक जिला स्तरीय विश्लेषण', आईडीई चर्चा पत्र संख्या 137।

• मुखर्जी एस. (2001): 'भारत में निम्न गुणवत्ता वाला प्रवासन: संकटग्रस्त प्रवासन और तीव्र शहरी क्षय की परिघटना', 24वें आईयूएसएसपी सम्मेलन, साल्वाडोर, ब्राजील, अगस्त में प्रस्तुत किया गया शोधपत्र।

• राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1991): 'प्रवासी श्रम पर अध्ययन समूह की रिपोर्ट', खंड II, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।

• ओबेरॉय और सिंह (1983): 'आंतरिक प्रवासन के कारण और परिणाम', नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

- पिंग, एच. (2003): 'चीन प्रवासन देश अध्ययन', बांग्लादेश शरणार्थी और प्रवासी आंदोलन अनुसंधान इकाई, बांग्लादेश/डीएफआईडी यूके, ढाका, 22-24 जून द्वारा आयोजित एशिया में प्रवासन, विकास और गरीब समर्थक नीति विकल्पों पर क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया शोधपत्र।
- राव, जी.बी. (2001): 'सूखा प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू मुकाबला/अस्तित्व की रणनीतियाँ: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक केस स्टडी', भारतीय बंजर भूमि विकास संवर्धन सोसायटी, नई दिल्ली।
- शांति, के. (1991): 'महिलाओं के आर्थिक प्रवास से संबंधित मुद्दे', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 34, संख्या 4।
- शैलेन्द्र एच.एस. और पी. थॉमस 1995: 'गैर-कृषि रोजगार: पश्चिमी भारत के अर्ध-शुष्क गांव में प्रकृति, परिमाण और निर्धारक', भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 50, संख्या 3, पृष्ठ 410-416।
- सिंह, डी. पी. (2009), 'गरीबी और पलायन: क्या स्थानांतरण मदद करता है?' कुंडू ए. (संपादक), भारत: शहरी गरीबी रिपोर्ट 2009, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सिंह, एस.पी. और आर.के. अग्रवाल (1998): 'ग्रामीण-शहरी पलायन: पुश और पुल कारकों की भूमिका पर फिर से विचार', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड 41 संख्या 4, पृष्ठ 653-667।
- स्केल्डन, आर. (2002): 'प्रवास और गरीबी', एशिया-प्रशांत जनसंख्या जर्नल, खंड 17, संख्या 4, पृष्ठ 67-82।

- श्रीवास्तव, रवि. एस. (1998): 'भारत में प्रवास और श्रम बाजार', भारतीय श्रम अर्थशास्त्र जर्नल, खंड 41, संख्या 4, पृष्ठ 583-616।
- सुंदरी, एस (2005): 'आजीविका रणनीति के रूप में प्रवास: एक लिंग परिप्रेक्ष्य', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 28 मई-4 जून।
- थान, एच.एक्स., डी.एन.अन्ह और सी. टैकोली (2004): 'वियतनाम के लाल नदी डेल्टा में आजीविका विविधीकरण और ग्रामीण-शहरी संबंध', माइमियो रिपोर्ट, नवंबर।